औद्योगिक व तकनीकी संभावना वाले शहरों का होगा कायाकल्प

अर्बन चैलेंज फंड से लखनऊ समेत सात शहरों का किया जाएगा विकास

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। केंद्रीय बजट के बाद प्रदेश के कई शहरों को औद्योगिक, बुनियादी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा सहित 7 शहरों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। वहीं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के नेशनल फ्रेमवर्क के तहत प्रदेश के टियर-2 और टियर-3 शहरों का भी विकास होगा। इसमें नोएडा, कानपुर और लखनऊ भी शामिल हैं।

एक लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड के तहत यूपी के सात शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी के अतिरिक्त तीन अन्य शहर शामिल होंगे। नेशनल ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (जीसीसी) फ्रेमवर्क के साथ यूपी में जीसीसी पॉलिसी जल्द कैबिनेट में पेश की जाएगी। इसमें क्षमताओं से भरे जिलों को पहले शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के कौशल विकास पर खास फोकस होगा।

बुनियादी ढांचे में विकास के लिए तीन वर्ष या इससे ज्यादा समयावधि वाले प्रोजेक्ट्स को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। प्रदेश में पीपीपी नीति जल्द लागू करने की तैयारी है। इसके तहत औद्योगिक विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी प्रकोष्ठ बनेगा। ये प्रकोष्ठ पीडब्लूडी, यूपीडा, शहरी विकास, आवास, मेट्रो, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और विकास प्राधिकरणों की उन योजनाओं को चिह्नित करेगा, जहां पीपीपी मोड के तहत काम किया जा सकता है। इन्वेस्ट यूपी इसकी नोडल एजेंसी है।

खास खबर

निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्तियों की होगी पहचान : संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत प्रदेश में निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्तियों की पहचान की जाएगी। इसमें बीमार इकाइयां, कॉटन व टेक्सटाइल मिलें और शहरी परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। संपत्ति मुद्रीकरण का मतलब सरकारी संपत्तियों के मूल्यों को अनलॉक कर सरकार के लिए राजस्व के नए स्रोत का निर्माण है। सरकार अपनी संपत्तियों को बेचने के बजाय इन्हें निजी कंपनियों को एक निश्चित अवधि के लिए लीज पर देती है।

निजी निवेशकों के लिए बनेगा मॉड्यूल : पीएम गतिशक्ति योजना के तहत औद्योगिक विकास विभाग निजी निवेशकों के लिए एक मॉड्यूल बनाएगा, जहां प्रदेश के औद्योगिक पार्कों, क्लस्टर, वित्तीय व सामाजिक सुविधाओं का जीआईएस डाटा होगा। सभी तरह की एनओसी के लिए इसे निवेश मित्र से जोड़ा जाएगा। अवस्थापना, औद्योगिक व एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक यूपी के औद्योगिक व बुनियादी विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से कई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा।

आठ लाख करोड़ का होगा बजट, विकास के योगी मॉडल की दिखेगी छाप

यूपी का बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह में

लखनऊ। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह में आहूत किया जाएगा। इसमें करीब आठ लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने की संभावना है। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। मध्यवर्ग, युवा, किसान और महिलाएं बजट के फोकस में होंगी। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, अभी सत्र की तिथियां तय नहीं हुई हैं। लेकिन, तैयारियां फरवरी के आखिरी सप्ताह को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। विभागों के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ब्यूरो

सेमी कंडक्टर इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में 100% छूट

लखनऊ। उप्र. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत सेमी कंडक्टर इकाइयों को 100% स्टांप ड्यूटी में छूट का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। स्टांप एवं पंजीयन विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक इस सेक्टर से जुड़ी इकाइयों के लिए जमीन खरीदने या लीज पर लेने के लिए स्टांप ड्यूटी पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। ब्यूरो